

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए गठित आयोगों का समीक्षात्मक अध्ययन

अरविन्द कुमार आर्य

सहायक प्राध्यापक, आदिनाथ कालेज ऑफ एजुकेशन, महर्षि ललितपुर

सार— 15 अगस्त सन् 1947 को भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया और भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना । भारत को आजादी के लिए एक लम्बा संघर्ष करना पडा । इसी प्रकार भारत में दी जाने वाली शिक्षा के भारतीय करण में भी लम्बा समय लग गया और अब भी प्रयास निरन्तर जारी है। आजादी के पूर्व से भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे परन्तु अंग्रेजी शासन होने के कारण प्रयासों में सफलता का प्रतिशत पश्चात इन प्रयासों को सार्थकता प्राप्त हुई और भारत सरकार ने इन प्रयासों को धरातल पर लाने का प्रयास भी किया । इन्हीं प्रयासों का अध्ययन कर हम उन महान विद्वानों को जान सकेंगे जिन्होंने भारतीय शिक्षा को यहाँ तक पहुँचाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1948 में डॉ.राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सन् 1952 में , डॉ.मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा सन् 1964 में डॉ.कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। सन् 1968 तथा सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा सन् 1979 में तैयार की गई ड्राफ्ट शिक्षा नीति । सन 2017 में के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिन्होंने 2019 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया और 2020 , अगस्त को केन्द्रीय समिति ने इस पास कर दिया, स्वतंत्र भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

संदर्भ सूची—

- 1 जैन.डा0 रोहित कुमार "आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार " HSRA Publication 2021
2. स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित शिक्षा आयोग – डा0 रोहित कुमार HSRA Publication 2020.
3. अल्लेकर ए. एस. "एजुकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया "
4. मुखर्जी आर. के. "एजुकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया". पृ. 55-56
5. बाशम ए. एल. "अद्भूत भारत "पृ. 193